[श्री रघुनाथ सिंह]

उसी की याद दिलाती है। मन्दिर का घंटा उसी का स्मरण कराता है। धर्मों के प्रति असहिष्णुता का अर्थ है कुरान के आदेशों को अवहेलना करना"।]

मैंने औरंगजेब के नाम शिवाजी महाराज का पत्र इस लिये यहां पर उपस्थित किया है कि उन्होंने औरंगजेब को बादशाह मानते हुए उन को एक सलाह दी थी कि आप में असहिष्णुता की भावना नहीं होनी चाहिये, आप में धर्म-निरपेक्षता की भावना होनी चाहिये।

अब मैं श्री गुरु गोविन्द सिंह द्वारा सुल्तान औरंगजेब को लिखे गए पत्र को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था :

"ईश्वर को पहचानना तुम्हारा कर्त्तव्य है। उसने दूसरों को सताने की तुम्हें आज्ञा नहीं दी है—किसी पर तलवार का वार जुल्म के साथ न कर, अन्यथा तू ऊपर से आने वाली कृपाण के प्रहार से बच न सकेगा। क्या जीवन का पौरुष कुछ ज्योतियों को बुझा देने में है।"

आज कहा जाता है कि साम्प्रदायिकता क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि श्री गुरु गोविन्द सिंह शब्दों में जीवन की ज्योतियों को बुझा देने का प्रयास ही साम्प्रदायिकता है। मैं गुरु गोविन्द सिंह की उसी परिभाषा को इस सदन के सम्मुख रखता हूं और कहता हूं कि इस से बढ़ कर साम्प्रदायिकता की कोई दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगली दफ़ा अपने भाषण को जारी रखें

17.10 hrs.

ADVANCE FOR BUILDING LINK BUILDINGS

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, इस पालियामेंट को जहां कुछ कानून बनाने और देश की सुरक्षा तथा वैदेशिक नीतियों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेने के अधिकार है। वहां इस देश की ग़रीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सरकारी कोष में आता है, उसकी सुरक्षा के लिये भी प्रबन्ध करना है। (*Interruptions*).

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य जरा ज़ोर से बोलें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस देश की पालियामेंट को जहां कुछ कानून बनाने का और देश की सुरक्षा का और वैदेशिक नीतियों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेने का विशेष अधिकार है वहां जो इस देश की गरीब जनता है और उसकी गाढ़ी कमाई का जो पैसा सरकारी कोष में आता है अथवा विदेशों से भारी शर्तों पर जो ऋण लिये जाते हैं, उन सब को सम्भालने और उसकी देख रेख करने का भी इस पालियामेंट को पूर्ण अधिकार है। अब से कुछ समय पूर्व २९ अगस्त को इसी सदन में मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसमें मैं ने यहां दिल्ली में मथुरा रोड पर जो भूमि है, उसके बारे में जानकारी चाही थी। इस भूमि के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ समय पूर्व इस प्रकार का निर्णय किया था कि जो समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं अथवा कुछ जनरल जो निकलते हैं, यदि वे अपने भवन यहां बनाना चाहें तो उनको रियायती दर पर कुछ स्थान दिये जायेंगे। उसी आधार पर कुछ पत्रों ने स्थान लिये थे। मुझे इस बात को कहते हुए दुःख प्रतीत होता है कि जो छोटे छोटे व्यक्ति अथवा पत्र ये जिन के पास कोई बहुत बड़ी सिफ़ारिश नहीं थी, वे तो भूमि प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके लेकिन जिन के पास अच्छे रिसोर्सिस थे उनको वहां पर स्थान मिल गया। इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि लिंक अखबार का अपना जो भवन बना है, उसके अन्दर क्या सरकार के किसी संगठन का भी कुछ पैसा, अगाऊ, धन के रूप में लगा है

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उप-वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया था कि ३ लाख ४४ हजार १३१ रुपये और २५ नए पैसे इंडियन रिफाइनरीज ने अगाऊ धन के रूप में इस भवन में कुछ स्थान किराये पर लेने के लिये दिए हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी सड़क के ऊपर कुछ ही गज पर इंडियन एक्सप्रेस की भी एक बिल्डिंग बनी है और उसके सम्बन्ध में शायद सदन को याद होगा कि कुछ समय पूर्व जब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का आफिस वहां खोला गया था और इसी प्रकार से अगाऊ धन के रूप में कुछ धनराशि दी गई थी तो किस प्रकार से उस समय इस सदन में क्षोभ और रोष व्यक्त किया गया था, इसको जो पुराने माननीय सदस्य हैं, ये भूले नहीं होंगे। उस समय सदन के माननीय सदस्य ने सरकार तक अपनी यह भावना पहुंचाई थी कि जब सरकार इतनी भारी भारी राशियां अगाऊ धन के रूप में दे कर किराये पर मकान लेती है क्यों नहीं वह अपने भवन बना लेती और उनमें से जो स्थान खाली रह जाये, उसको औरों को किराये पर उठा देती ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे माफ करें अगर मैं एक मिनट के लिए कुछ कह दूं। म बता देना चाहता हूं कि पांच बज कर दस मिनट पर यह डिसकशन शुरु हुआ है। मैं माननीय सदस्य को दस बारह मिनट से ज्यादा नहीं दे सकूंगा और दस बारह मिनट ही मिनिस्टर साहब को बोलने के लिए दूंगा। पांच छः मैम्बर साहिबान ने सवाल पूछने के बारे में नोटिस दिए हैं, उनको भी मैं सवाल करने के लिए एक एक मिनट से ज्यादा नहीं दे सकूंगा इस वास्ते माननीय सदस्य दस बारह मिनट में खत्म कर दें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां, मैं दस बारह मिनट में समाप्त कर दूंगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस समय इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का कार्यालय खोला गया था तो उस वक्त जो रोष व्यक्त किया गया था वह, जो पुराने माननीय सदस्य हैं, उनको याद होगा। यह कहा गया था कि सरकार अपनी ओर से इस प्रकार के मकान क्यों नहीं बनवाती ? लेकिन इतना होने पर भी और इस सदन की भावनाओं को जानते हुए भी एक सरकारी संगठन की ओर से इतनी भारी राशि का वहां दिया जाना समझ में नहीं आता है और पता नहीं क्यों सरकार इस सदन की भावनाओं का तिरस्कार अथवा निरादर करती है।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को जो एक्सप्रेस बिल्डिंग में स्थान दिया गया था इसीलिए रियायती दर पर सवा लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो भूमि दी गई थी सरकार ने उस भूमि का मूल्य बढ़ा कर के भूमि का मूल्य बढ़ा कर के बाद में सोलह लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लिया लेकिन इसके साथ ही साथ सदन की जानकारी के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि यह जो यूनाइटेड इंडिया पीरियोडिकल्ज लिमिटेड कम्पनी है जिस की ओर से यह पत्र निकलता है इसको पांच लाखमें रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि दी गई। जानना चाहता हूं कि आखिरकार उस भूमि पर जो भवन बनाना था उस में से कोई खास किस्म की खुशबू आनी थी या खास हवा बहनी थी कि इस सस्ते दर पर दी गई जबकि चंद गज के फासले पर सत्तरह लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जगह गयी और वह भी उन व्यापारिक संस्थाओं को जो कि इसी प्रकार किराये पर उठाते हैं और उसके ही बग में इस प्रकार का भवन बनाते हैं। उसको पांच लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि दी गई और ढाई लाख में आधा एकड़ जमीन उसको दी गयी। यह जो जहांगीरी इंसाफ

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

उसके साथ किया गया है, उसके क्या रहस्य हैं ? साथ ही साथ एक और बात भी जानने की है । अगर मैं कुछ प्रसंग से बाहर न चला जाऊं तो मैं कहूंगा कि इस देश में कुछ साप्ताहिक पत्रों की नीति इस प्रकार की हो गई है कि वे सरकार की मशीनरी में एक दो व्यक्तियों की तो विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं और फिर उसकी आड़ ले कर सरकारी नीति और सरकार की जी भर भर के आलोचना करते हैं, और तिरस्कार करते हैं । क्या किसी एक ऐसे ही पत्र को इस प्रकार से रियायती दर पर भूमि देना और बाद में चल कर के भवन निर्माण के लिए भारी राशि देना, न्याय संगत हो सकता है और अगर हो सकता ह तो कहां तक हो सकता है, यह मैं जानना चाहूंगा ।

सब से बड़ी हैरानी की बात तो यह है जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि इसी एक्सप्रेस बिल्डिंग में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के कार्यालय के लिए जो स्थान दिया गया है, उसके लिए उससे ६० नए पैसे प्रति स्क्वेयर फीट किराया चार्ज किया गया है । लेकिन इस लिंक हाउस में जहां इंडियन रिफाइनरीज का आफिस खोला गया है जिस के बारे में प्रश्न उत्तर में उप-वित्त मंत्री ने बताया है कि सोलह प्रतिशत हम को कंसेशन दिया गया है किराये में । जो किराया वहां दिया जा रहा है वह एक रुपया पच्चीस नए पैसे प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से दिया जा रहा है जब कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो कि नई दिल्ली की सब से मुख्य सड़क मानी जाती है, सरकार की एक कम्पनी, इंडियन ड्रग्ज कम्पनी है, वह बिना एडवांस के जो किराया देती है वह एक रुपया प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से देती है । ऐसी स्थिति में सोलह प्रतिशत की उदार छूट देने का अभिप्राय क्या यह तो नहीं था कि वह मनमाना किराया इंडियन रिफाइनरीज से प्राप्त करना चाहते थे, जहां तक हो सकता था परिचय का लाभ उठाना चाहते थे ?

इसी इंडियन रिफाइनरीज का दफ्तर पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर जो स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, उस में था । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि वह अपने उत्तर में बतायें कि उस समय क्या किराया दिया जाता था और क्यों इतना महंगा किराया दे कर के वह फिर भी एहसान लिया गया है कि सोलह परसेंट की छूट इसमें हुई है ।

जब यह धन दिया गया और जब तक यह आफिस उस बिल्डिंग में नहीं गया था, तो क्या इस बीच में छः महीने का अवसर दिया गया था और अगर दिया गया था तो क्यों नहीं उस अवधि में यह आफिस वहां चला गया और क्यों प्रतिमास ७,१६६ रुपये के हिसाब से ४२,९९६ रुपये हानि उठाने की नौबत आई । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? छः महीने तक यह आफिस त. वहां नहीं गया और पैसा उनकी जेब में चला गया, तो क्यों नहीं पहले वह आफिस वहां चला गया, यह मैं जानना चाहूंगा ।

चार साल का जब किराया एडवांस दे कर के लिंक हाउस में जगह ली गई, तो उसी समय इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन की बिल्डिंग भी बन रही थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया था कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया जाए और उसमें इंडियन रिफाइनरीज के लिए जगह लेने की कोशिश की जाए और पता लगाया जाए कि वहां जगह मिल सकती है या नहीं मिल सकती है और अगर मिल सकती है तो किस किराये पर मिल सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि उसको छोड़ कर के लिंक हाउस में विशेष रूप से क्यों जगह ली गई ।

एक और जिस आश्चर्यजनक बात ने मस्तिष्क में आ कर के सन्देह पैदा किया है

वह यह है कि यह पत्र जिसका सीमित क्षेत्र है और कुछ हजार की संख्या में ही निकलता है इस पत्र ने चालीस लाख रुपये की अपनी बिल्डिंग को कैसे खड़ा कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार की यह नीति है कि उस सड़क पर उन्हीं संगठनों को भूमि दी जाए जो समाचारपत्र प्रकाशित करेंगे न कि उस जगह को किराये पर उठायेंगे तो क्या वजह है कि आज उस चालीस लाख के विशाल भवन के एक कोने में तो इस समाचारपत्र का कार्यालय है और बाकी का सारे का सारा जितना स्थान है, उसको वह किराये पर उठाये हुए है। एक ओर तो सरकार स्वयं यह नीति घोषित करती है कि उस सड़क पर केवल उन्हीं को स्थान दिया जाएगा जो समाचार-पत्र प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर सरकार के ही कार्यालय उन में जा कर के किराये देते हैं और सरकारी नीति की अवहेलना करते हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार से सरकार कैसे अपनी नीतियों को सुरक्षित रख सकेगी।

प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया है कि जो शर्तें लिखी हैं, उनको कुछ उदार बनाया गया है, उनमें कुछ सहूलियतें दी गई हैं और उसी में इतनी भारी राशि उसको दी गई है। जहां तक इन शर्तों का सम्बन्ध है, जो सोलह प्रति शत वाली बात है वह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक और कमजोर शर्त की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। उस में सब से कमजोर शर्त यह है कि इस इमारत का पट्टा तीन महीने के नोटिस पर खतम किया जा सकता है। इतनी भारी रकम लगाने के बावजूद भी यह कहा गया है कि ये जब चाहें तीन महीने का नोटिस दे कर इंडियन रिफाइनरीज को वहां से निकाल सकते हैं। ऐसी हालत में मैं नहीं समझ पाया हूं कि सरकारी धन की रक्षा कैसे हो सकती है और जो गरीब जनता का धन यहां आता है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि वह अपने उत्तर में बतायें कि जो इतनी भारी राशि वहां लगाई गई है, उसके लिए क्या वित्त मंत्रालय से स्वीकृति ले ली गई थी या वित्त मंत्रालय ने इस के सम्बन्ध में, कोई नीति निर्धारित की हुई है और यदि की हुई है और उसका पालन नहीं किया गया है तो किस तरह से इतनी भारी राशि वहां पर लगा दी गई।

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। यह जो अखबार है यह पहले थेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग में चलता था। उस समय देहली की एक तथा कथित सम्मानित महिला जिन्होंने काश्मीर कमेटी के नाम पर कुछ कमरे एस्टेट आफिस से किराये पर लिए हुए थे, उनमें इस अखबार का कार्यालय इन्होंने रखा हुआ था। फिर यह अखबार उसके पश्चात् हटकर मथुरा रोड़ गया। इस अखबार की नीति के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूं तो वह प्रसंग के बाहर की बात होगी। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अखबार के जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज हैं, जो उनकी नीति है और जिस आधार पर उन्होंने पत्र चला रखा है उससे प्रभावित हो कर के तो माननीय मंत्री जी ने कहीं इतनी बड़ी धनराशि तो वहां नहीं लगा दी है।

यह एक सन्देह है जो आज हर मस्तिष्क को बेचैन कर रहा है, और मैं चाहूंगा कि इस चर्चा का उत्तर देते समय, इन बातों का स्पष्टीकरण भी किया जाय जिस से कि यह चर्चा सदन के माननीय सदस्यों को ही सन्तोष न दे सके बल्कि देशवासियों के लिये सन्तोषजनक हो सके।

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): A part of Shri Prakash Vir Shastri's question reads as follows.

> "whether there has been any tradition in public sector industryies to make advances of such huge amounts of money and whether Government have laid down certain rules in this regard."

[Shri Hari Vishnu Kamath]

for which the answer was:

> "No such specific instructions have been issued by Government in this connection."

May I ask if this is the solitary instance of a magazine or a periodical or a journal or a newspaper in India to which such financial assistance has been advanced from the public sector institution or ...... (*Interruptions*) there are any others to which such assistance has been rendered and if so how much money and to what journals?

Mr. Speaker: Shri Banerjee—absent Shri Dwivedy.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Is it not a fact that apart from the Indian Refineries Ltd. a contract is given to the Kalinga Airlines at a special concession rate to drop food supplies in NEFA area with the understanding that a substantial amount of its profit would be advanced to LINK buildings and it has been done?

Shri Morarka (Jhunjhunu): On 16th March 1961 in answer to my question about the accommodation for State Trading Corporation in the Express Buildings, I was told that the rent was Rs. 0·60 nP. per sq. foot and when the question was raised the hon. Minister said that this rent was fixed in consultation with the Ministry of Works, Housing and Supply and the Ministry of Finance. In this particular instance, I find the rent is more than double, Rs. 1·25 per sq. foot. Has this rate of rent also been fixed with the consent of the Ministries of Finance and W.H.S.?

Shri Joachim Alva (Kanara) *rose*—

Mr. Speaker: Did he give notice?

Shri Joachim Alva: Yesterday I gave notice.

Shri Joachim Alva: When the hon. Minister came to this decision, did he take an overall view of the state of journals in India and was he guided by the Press Commission report that most journals die a quick death through debts and mortgages?...... (*Interruptions*).

Mr. Speaker: No speech is allowed. Only one question.

Shri Joachim Alva: I want to know whether very heavy loans have been advanced to a single newspaper combine amounting to even half a crore of rupees through any agencies of the Government and when such loans have been given to any newspaper...

Mr. Speaker: Order, order. I will ask the Minister to answer only one question.

Shri Joachim Alva: The third question is: what other facilities have been drawn by the five large newspaper combines of India in several shapes and forms.... (*Interruptions*).

Mr. Speaker: The hon. Member does not listen to my request....

Shri Joachim Alva: I will sit down with my last.

Mr. Speaker: I have allowed him only one question as I have done in the case of others. He cannot make a speech.

Shri Joachim Alva: I want the hon. Minister to give us the background.

Mr. Speaker: Not during the half an hour discussion. No background can be given; only the front ground.

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): May I know how Indian Refineries came into contact with this organisation for renting out this building? Was it through the intervention of the Minister concerned? What previous investigations were made before they finally struck this bargain which *prima facie* does not look very fair?

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) *rose*—

(a) Whe... of 'Gram ...

Mr. Speaker: Hs was not in his seat when I called him.

Shri S. M. Banerjee: It is most unfortunate.

Mr. Speaker: It is most unfortunate that he wants to be called again.

Shri S. M. Banerjee: Is the entire fourth floor occupied by the Government free of rent for four years and that is one of the terms?

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of procedure. The main answer to this question out of which this discussion has arisen was addressed to the Finance Minister and answered by him. Now we have only 10-15 minutes left. Will you kindly apportion the time between the Minister of Finance and the Minister of Mines and Fuel who will answer some questions. Some questions can be answered only by the Finance Minister and the hon. Minister of Mines and Fuel will probably say that he has no information.

Mr. Speaker: I expect the Minister who replies to answer all the questions.

Shri Hari Vishnu Kamath: I hope so.

Mr. Speaker: I also join him in hoping.

Shri Hari Vishnu Kamath: But I am sure he will not answer some of them.

The Minister of Mines and Fuel (Shri K. D. Malaviya): Mr. Speaker, I would start by answering the question of Shri Mathur that long after the negotiations had started between private limited company, Indian Refineries Limited, and the United India Periodicals Private Limited, I knew of these negotiations. In the early stages, I was not aware of it because the Indian Refineries are perfectly entitled to search for their own accommodation and to rent a building. It is one of their functions and they were thoroughly entitled to do it. There was nothing to ban them from searching and finding out accommodation in a building which was owned by the United India Periodicals Limited which supports a policy advocated by the Government of India in certain respects. I will, however relate the circumstances which have led to the Indian Refineries taking the building in question for their office.

Immediately after the incorporation of the company in 1958, the company hired office accommodation in the Sunlight Insurance Building in the Delhi Ajmere Gate extension area and after about a year or so, acquired more suitable and centrally situated accommodation in the third floor of the State Bank building in the Parliament Street. The area of accommodation occupied in the State Bank building was 5238 sq. ft. and the rental payable, Rs. 0·75 nP. per sq. ft. Since 1959-60 the work of Indian Refineries Limited expanded and increased enormously and a large number of technical staff was required initially posted to Delhi to assist the managing director and the board of directors in the detailed discussions with the Rumanians. They therefore required accommodation larger than what was available in the State Bank building. Furthermore, the managing director of the Indian Refineries Limited was also at this stage appointed as member (refinery) in the Oil and Natural Gas Commission and as such he was entrusted with the task of organising another refinery in Gujarat which required a large number of staff and owing to this the work of Gujarat Refineries entrusted to the managing directors of the Indian Refineries Limited meant great economy and saving for the ONGC. Just a few weeks after the Indian Refineries were entrusted with the preliminary work relating to the product pipeline construction, its study and also the preparation of the detailed project reports relating to the lubricating oil projects as well as refinery that may be located by Government of India in South India.

[Shri K. D. Malaviya]

All these needed more staff both technical and administrative and it was impossible for the Indian Refineries Limited to stay in the State Bank buildings which had only 5,000 and odd sq. ft. accommodation. When the need for accommodation was felt towards the close of 1960 in order to accommodate a larger number of staff, technical as well as administrative, the company approached the Director of Estates, Government of India in December 1960 for securing office accommodation in Rail Bhawan. They refused because there was no accommodation. In the circumstances the company issued a general enquiry through local papers for obtaining the requisite office accommodation. The response to the advertisement was however very poor. On independent informal enquiries for accommodation in various localities throughout Delhi, old Delhi and New Delhi, no suitable accommodation was available for enabling them to work on technical schemes. Places were searched in the Diplomatic Enclave, Jor Bagh, Parliament Street, Darya Ganj, Asaf Ali Road, etc., but no suitable accommodation was found.

Shri Surendranath Dwivedy: Even the Life Insurance Corporation refused?

Shri K. D. Malaviya: It did not come at that time. While the company was still looking for additional accommodation, the United India Periodicals, Ltd., the proprietors of the Link House, made an offer on their own in April, 1961, reporting availability of office accommodation in their building which was then under construction. In their offer they had quoted a rate of rent for the different floors and also qualified their offer that an advance covering the rent for a period of four years would be necessary in order to facilitate the completion of the building by October, 1961.

Up to that stage the Government was not aware of any details or negotiation between the Indian Refineries, Ltd., and the United India Periodicals, Ltd. Such an advance of rent is admissible under the Delhi Rent Control Act i.e., those who invite people to hire their building are entitled to ask for advance rent. Therefore, there was nothing to bar the Indian Refineries from negotiating on that basis. They had no accommodation; their staff was increasing and their work was suffering. There was only one alternative: to leave Delhi. Or, there was another alternative, namely, to construct a building. It meant they would have to wait for a couple of years. That matter also should have been of great concern to this House. Therefore, they had to choose between accepting the offer and to think of going somewhere else, if they were not able to get a house. It meant going out of Delhi or not doing the job at all. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order.

Shri K. D. Malaviya: The rates offered by the United India Periodicals were scrutinised with the prevailing rates in the Parliament Street as well as in the neighbourhood of the Link House such as Asaf Ali Road, Indian Express Building, etc., I do not wish to enter into the circumstancs in which the Indian Express Building was constructed. It was by arrangement with the Government of India. It was quite a separate arrangement.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Why not it be referred to?

Shri K. D. Malaviya: When the Government of India allowed the Link

(a) whe... ...tion of 'Gram ...

Building to be put up there the arrangement was that the entire fourth floor was to be occupied by the Government of India free of rent, and it was to be occupied not for one or two years but for four years. This condition formed part of the terms. Otherwise, they would not be allowed to construct the building. The United India Periodicals paid a premium of Rs. 2·5 lakhs and is now paying ground-rent of Rs. 6,260 or so. These are the conditions on which they were allowed to erect the building. There was only one alternative for us because there was no other place for accommodating the office of the I.R. Ltd. They carried on negotiations with the Link House owners. In Parliament Street, the Indian Oil Company had hired office accommodation at Rs. 1:20 nP. per sq. ft. . . .

Shri Prakash Vir Shastri: What about the Indian Drugs, Ltd.?

Shri K. D. Malaviya: .... and the Heavy Electricals Ltd. at Rs. 1·50 nP per sq. ft. Both the companies were getting accommodation in the same building and they were not of the same size. In the Indian Express Building, the State Trading Corporation are paying much less—Rs. 60·00 per 100 sq. ft. But this is so under special circumstances and in 1956. The hon. House knows about those circumstances in which it was done. (*Interruptions*). The other occupants in the Indian Express Building, Messrs. Larson and Toubro and Messrs. Hindustan Levers, are paying Rs. 100·00 per 100 sq. ft. and Rs. 80 per 100 sq. fat. respective. They have been in occupation of the building for some years now and are paying more than the State Trading Corporation. LIC are also putting up another building in Parliament Street, for which at that time the rent was not fixed, but for which it was informally known that the rent would be between 100 to 150 nP per 100 square feet. At that time it was not available to the ndian Refineries Limited.

It will, therefore, be observed that not only suitable accommodation was available, but that the rates of rentals varied from place to place. It depended upon the two parties agreeing to a particular condition acceptable to both of them. The main question was to get the accommodation to do the work and to see that the work does not suffer. That was the main thing. There were no political issues involved in it, and the Government did not come into it. Those who were charged with the task of running the work had to be left with the responsibility of finding out their own accommodation.

I now come to conditions. After making detailed investigations, the Indian Refineries Limited negotiated with the United India Periodicals and as a result thereof acquired an area of 6828 square feet at the rate of 125 nP per 100 square feet, less 16 per cent discount thereof, in consideration of four years' rent being paid in advance. The lease agreement was executed with the United India Periodicals and accordingly an amount of Rs. 3,44,131·25 nP was paid in advance to cover the rent for four years, effective from 1st January 1962. In this connection some distortion of fact was made by Shri Shastri. As a further safeguard, the Indian Refineries Limited secured an agreement with the proprietors of Link House to the effect that in the event of the company vacating the premises before the expiry of four years, the Indian Refineries Limited would have the option to obtain refund of the balance —is that clear to Shri Shastri?—or alternatively to retain the lien or the right of subletting the premises. Therefore, there was no question of any loss to the Indian Refineries Limited. They had assured themselves, because they are a business body that they would not have to suffer any loss. The lease of the premises can also be otherwise terminated by three months' notice on either side.

[Shri K. D. Malaviya]

The rebate of 16 per cent secured in the advance rent paid by the company is not unfavourable as compared to the rent paid by the Delhi Electric Supply Undertaking—they are also accommodated there—and the Nestles Company, who are occupying accomodation on the same floor as the Indian Refineries Limited. The Delhi Electric Supply Undertaking have been given a rebate of 5 per cent against an advance of one year's rent and the Nestles Company have been given a rebate of 12 per cent against an advance of 4 years' rent. They were all business concerns. They all got into Link building without caring whether the Nestles Company owners were against the policies of *Link* or not. Politics did not come into it. What was relevant was for them to get accommodation in order to carry on their business. In that way, the Indian Refineries also followed the business aspect.

The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking too had agreed to an arrangement to pay rent for 4 years to the Union Bank of India Limited, the latter bank making an advance to the United India Periodicals of a sum equal to four years' rent in advance. So, we were not alone to pay rent in advance. It was done according to business principles and there was nothing wrong in it.

Further the interest that could have accrued on Rs. 3·44 lakhs of capital which was advanced to them would have, at the rate of 6 per cent, amounted to Rs. 51,600. But the rebate that was obtained at the rate of 16 per cent amounted to Rs. 65,548. We got more on the investment of that capital than what would have been the interest. So, even looking at it from the business point of view the Indian Refineries Limited have earned more money on their investment of Rs. 3·44 lakhs than many others. I do not understand how this House or the Government could have prevented them, under the existing rights enjoyed by them, to employ their capital in order to earn some money. It was not only 6 per cent, but they earned something more than that.

Shri Hari Vishnu Kamath: It was a good investment.

Shri K. D. Malaviya: Was it open to this House or for the Government to have stood up and said that they cannot get the accommodation because some of the Members of the House would be opposed to the public sector policy of the Government and, therefore, they would come up at some moment and object to it?

Shri Hari Vishnu Kamath: He is misleading the House.

Shri K. D. Malaviya: I am not yielding.

Shri Surendranath Dwivedy: The House is entirely in favour of public sector industries.

Shri K. D. Malaviya: I am referring to the hon. Member who raised this discussion. He is not in favour of our public sector policy.

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, I rise to a point of order. You permitted us to participate in this discussion. He has no business to say that we are not concerned with it. He is wholly wrong in misleading the House. (*Interruptions*).

Shri K. D. Malaviya: I may repeat in the end......

Mr. Speaker: When we are about to adjourn there ought not to be such excitement.

Shri Hari Vishnu Kamath: He has provoked me.

Shri K. D. Malaviya: My hon. friend goes on provoking all the 365 days in a year. Let him give me permission to provoke him one day.

Shri Hari Vishnu Kamath: Absolute nonsense, Sir.

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member goes on......

Shri Hari Vishnu Kamath: The Minister is here all the 365 days; I am not here.

Mr. Speaker: When we give to others we ought to be prepared to take also. We are going on in a very lighter mood, and he should not be so serious.

Shri K. D. Malaviya: Lastly, I want to re-emphasise the point, that the arrangement made between the Government of India and this corporation which erected this building was on the ground that they would give one floor free of rent for four years. That must have weighed before those people who negotiated with the Indian Refineries Limited. Indian Refineries Ltd. is a private limited concern owned by the Government of India. I do not think the Indian Refineries Limited stood as a loser in this transaction.

Sir, I repeat that the periodical *Link* has generally advocated the policy which is propagated by the Government of India and as such we do not think, even at a later stage when it was known to us, that we should have objected to a legitimate decision of I.R. Ltd.

Shri Hem Barua (Gauhati): The policy of *Link* is crypto-communist and the Minister is a subscriber.

Shri Surendranath Dwivedy: You have subsidised a paper advocating Government's policy.

Shri Hari Vishnu Kamath: Does the Prime Minister agree with it?

Shri K. D. Malaviya: I think, Sir, I have narrated under what circumstances the office was accommodated in the Link building (*Interruptions*).

Mr. Speaker: The Half-an-hour Discussion is over. The House stands adjourned *sine die*. My good wishes to everyone.

17.44 hrs.

The Lok Sabha then adjourned sine die.